

सम्पादकीय

मोदी सरकार के आत्मनिर्भर
भारत अभियान का विचार बजट
से पकड़ेगा और तेज रफ्तार

मंगलवार को पेश हुए आम बजट की भीमांसा जारी है। इसमें कई बिंदु उभरकर आ रहे हैं। फिर भी अगर उसके सार तत्व की बात की जाए तो यह पारंपरिक परिपाठी से इतर ताजगी का अहसास करने वाला बजट है, जो आसन्न चुनौतियों से निपटने एवं दस्तक दे रही सभावनाओं को भनाने की आधारशिला रखता है। डिजिटल मोर्चे को और मजबूत करने की सरकारी रणनीति से यह साबित भी होता है। मोदी सरकार इसके लिए निश्चित रूप से सराहना की पात्र है कि उसने चुनावी दौर में लोकभूमध्यान धोषणाओं का मोह न करते हुए प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायता सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने राजनीतिक जोखिम लेने से भी गुरेज नहीं किया। आदर्श जीवन का मूल मंत्र यही माना जाता है कि अपने दायरे का विस्तार करने से पहले अपनी विद्यमान क्षमताओं को उनके उच्चतम स्तर तक पहुंचाना श्रेयस्कर होता है। बजट में सरकार ने इसी दर्शन को आत्मसात किया। उसने मात्रा बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक बुनियादी ढांचे से जड़ी आंगनवाड़ी जैसी पहल को ही लें, सरकार ने ऐसे और केंद्र स्थापित न कर मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों के उनन्यन को प्राथमिकता दी। रेलवे में भी इसी नजरिये की झलक मिलती है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेज रफ्टर 400 नई वेदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ियां भारत की विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता का उद्घोष करने वाली हैं। वही रिजर्व बैंक के माध्यम से डिजिटल मुद्रा की धोषणा दर्शीती है कि सरकार नए तक की धून के साथ ताल मिलाने की आवश्यकता और उसमें नागरिकों के हितों के संरक्षण को खब्बी समझती है। बजट में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण गतिविधियों को गति देने पर विशेष जोर है। इसमें राज्यों को भी आगे आने का अवसर दिया है, जो केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाने का सूत्र बन सकता है। इसी कड़ी में केंद्र राज्य सरकारों के साथ औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का प्रस्ताव लाया है। इससे विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर के केंत्र रोजगार की चुनौती का समाधान निकलेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता घटने एवं निर्यात बढ़े का मार्ग खुलेगा। सरकार की नई पहल विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेंज जैसी अनुपादक योजना के मुकाबले काफी सभावनाशील लगती है। पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी के उच्च गुणक प्रभाव से भी आर्थिक मोर्चे पर बड़ा लाभ होने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 25,000 किमी राजमार्ग निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना खासी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होगा कि रोजाना 70 किमी राजमार्ग का निर्माण। यह ऐसा लक्ष्य है जिसे चीन ने भी अपने बुनियादी ढांचा विकास के चरम में कभी हासिल नहीं किया। चीन का अधिकतम औसत 35 किमी राजमार्ग प्रतिदिन निर्माण का रहा है। मल्टी माइल कोरिटिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की योजना भी गेमचेंजर साबित हो सकती है। इसमें नदी मार्ग एवर कार्गी, शिंगिंग और रेलवे को भी शामिल किया गया है। इसके तहत विकसित किए जाने वाले 100 कार्गी टर्मिनल बेहतर लाजिस्टिक दक्षता सुनिश्चित करेंगे। क्लीनेटक मैन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कारोबार के प्राथमिक एडोने में शामिल हैं। इसमें बैटरी स्टैंपिंग जैसे कदम उठाए गए हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में पालीसिलिकान सौर माड़यूल निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक हील कल यानी ईवी निर्माण को प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च, 2024 तक नई घरेलू विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कर व्यवस्था का विस्तार ईवी और ईवी घटकों में अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त बजट डेटा केंद्रों के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लीनेटक बनियादी ढांचे और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए आसानी से वित्तोपेषण उपलब्ध हो। वित्त मंत्री ने कृषि बुनियादी ढांचे पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। कृषि आपूर्ति शृंखला एवं लाजिस्टिक को सशक्त बनाने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की दिशा में आवश्यक उपकरणों पर आयात शुल्क को भी आकर्षित बनाया गया है। देश को रक्षा उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस दिशा में घरेलू रक्षा उत्पकरण उत्पादन के लिए पूंजीगत व्यय में 68 प्रतिशत की अभूतवूर्ध वृद्धि अपेक्षित परिणाम लाएगी।

**उत्तर प्रदेश विधानसभा
चुनाव में उपयोगी साबित
होगा एयरपोर्ट और
एक्सप्रेसवे वाला एजेंडा**

उत्तर प्रदेश में सीमित और नए तौर-तरीकों के साथ चल रहे चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी का 'ज़ंगलाराज' और बहुजन समाज पार्टी का 'जाप्रदाइ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ' के निशान पर है। वह जब मतदाताओं से अपनी बात कहते हैं तो अपने बात के समर्थन में उन प्रसंगों और घटनाओं की याद भी दिलाते हैं जो तीहास में दर्ज हैं और किसी स्तर पर आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं। कर्णाना का पलायन, मुजफ्फरनगर दर्गा की जड़ कवाल कांड, बम धमाकों के अभियुक्तों से कथित हमर्दी जैसे मसले उठाकर वह समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की याद दिलाकर भ्रष्टाचार के बड़े मामलों और जातीय सियासत के खतरों को सामने रख देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एंडेंस साफ है। वह हर हाल में लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षा का अहसास दिलाना चाहते हैं और राजकाज के लिए इसे ही सबसे बड़ी कर्तृती मानते हैं। वास्तव में यह सुरक्षा ही प्रगति का आधार है, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेसवे टोल पुजा में गुंड़ई के साथ व्यर्थ है। कोई शहर साप्रदायिक तनाव के बीच कारोबार की उम्मीदें नहीं जगा सकता। असुरक्षा का अहसास न तो युवाओं का उनके भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकता है और न महिलाओं को उनके सशक्तीकरण के प्रति। उसे सकारात्मक रुख : अक्सर समाजवादी दृष्टिकोण उद्योगीकरण के प्रति नकारात्मक भाव रखता नजर आता है। यह दृष्टिकोण शायद यह देखने से इकार करे कि जेवर में बनने जा रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना 15 साल से ज्यादा समय तक दिमाग और कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी का भी राज रहा और बहुजन समाज पार्टी का भी। सपा को क्षेत्र में सियासी समीकरण देखने थे तो बसपा को अपने हित। किसी ने केंद्र पर आरोप लगाया तो किसी ने जमीन न मिलने का रोना रोया। यह योगी थे जिन्होंने इसकी अहमियत और जल्लरत समझी और इस योजना को धारातल पर उतारने का काम किया। जेवर ग्रेटर नोएडा में है, जिसकी अपनी पहचान है, अपने उद्योगों के साथ राष्ट्रीय राजधानी से नजदीकी की विशेषता इसे और अहमियत देती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद वे शहर हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से भी भरे हुए हैं। लोग काम-धैर्य और रोजगार की चाहत में आते हैं और अपने घरों को याद रखते हुए भी यहीं के हो जाते हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट विकास के दो काम भर नहीं हैं। ये वर्षी या फिर कहें कि दशकों की समस्याओं के दलदल से निकले हैं, जो कारोबार के साथ-साथ जीवन की सुगमता के माध्यम भी बन गए हैं या बनने वाले हैं। ऐसे विकास कार्य एक या दो विधायिकों को नहीं जिताते, बल्कि सत्ता का आधार बनाते हैं।

पर्वतमाला परियोजना के तहत कैसे देगी भारत सरकार पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को धार

तैनाती के लिए हर भारतीय सैनिक के पास पर्वतारोहण का 'अनिवार्य स्किल' है। वहीं 'मार्डन वीपनरी मैग्जिनेट' के सीनियर एडिटर हुआंग गुआँझी ने भी कहा था, 'वर्तमान में मैदानी और पर्वतीय इलाकों में दुनिया की सबसे ज्यादा अनुभवी सेना अमेरिका, रूस या युरोपीय महाशक्ति के पास नहीं, बल्कि यह भारत के पास है।' पर्वतमाल का उद्देश्य : पर्यटन भारत जैसे विकासशील देश के जीडीपी ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण

के कुछ राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला को पीपीपो मोड से चलाया जाएगा। इसी साल यानी 2022-23 में इन पहाड़ी राज्यों में 60 किमी लंबे आठ रोपवे परियोजनाओं को शुरू किया जाना है। पर्वतीय राज्यों में सड़क निर्माण काफी कठिन होता है। ऐसे में रोपवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे। इन रोपवे परियोजनाओं को आधुनिक तकनीक से तैयार किया

पतिक्रमण की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल आजादी के 74 वर्षों में सीमान्त गांवों अथवा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित चंद्रेनश्शील क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा यानीति की मुख्यधारा में नहीं आ गए थे। इस देश में आदिवासी अथवा बनजातीय क्षेत्रों नक्सल और आवोदार प्रभावित क्षेत्रों के समावेशी विकास पर भी काफी देर बाद ही बल देया जाना शुरू हुआ। इसके चलते भारत के कुछ पड़ोसी देशों खासकर पृजन और पाकिस्तान के भारत विरोधी

सूजन करने के प्रयास तेज हुए हैं। उत्तराखण्ड के युवा मुख्यमंत्री पृष्ठकर सिंह थामी ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों पर विशेष तौर से फोकस करने की रणनीति बनाई है। थामी सरकार की पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ी रणनीति में सीमांत गांवों से पलायन को रोकने और पलायन से खाली हो चुके गांवों में ग्रामीणों को पुनः बसाने पर स्मोर्वेनिया की तरह जोर दिया गया है। गौरतलब है कि स्मोर्वेनिया अपने कुल राजस्व

राजनायिक संबंधों की स्थापना के बाद से लगातार प्रगाढ़ हो रही इजरायल-भारत मैत्री

इन दिनों हम इजरायल और भारत के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले वर्ष सिंतबर में इजरायल के राजदूत के रूप में अपनी रोमाचक यात्रा शुरू करने के लिए मैं नई दिल्ली पहुंचा था। इजरायल के राजनयिकों के लिए भारत सभेसे फिल्हासी और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, क्योंकि भारत में इजरायल के कई मिमांसा भी उत्पीड़? या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सबको अपनाने गला भारतीय समाज उन्हें फलने-फूलने और अपना अभिन्न आंग बनने की इजाजत देता है। इसे ही हम 'अतुरुत्य भारत' के रूप में जानते हैं। बीते 30 वर्षों के दौरान भारत के साथ इजरायल के द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में प्रगाढ़ हुए हैं। स्वास्थ्य, कृषि, जल, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीकी अन्वयनशाली पर्यावरण

साइबर ठगी से बचाव के साथ संबंधित संगठनों की तय हो जवाबदेही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व न्यायाधीश पूनम श्रीवास्तव के बैंक खाते से ज़ारखड के साइबर अपराधियों द्वारा पांच लाख रुपये की ठांगी के सभी आरोपियों की ज्ञानत अर्जी खरिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि साइबर ठांगी के मामले में पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए। अदालत ने माना कि बैंक में पैसा जमा करने वाले देश के प्रति ज्यादा ईमानदार हैं। हर हाल में उनका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कालाबाजारी करने वाले लोग पैसा तहखाने में रखते हैं, जो देश के विकास में काम नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि बैंक यह कहकर नहीं बच सकती कि वह इसके जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ ही पुलिस भी यह कहकर नहीं बच सकती कि साइबर अपराधी उनको पहुंच से दूर नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं। एक बात तो तय है कि इस एक उदाहरण के अलावा भी ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं जिनमें साइबर ठांगी

गया है। साइबर ठांगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इस पर नियंत्रण का काम शुरू किया। इधर जैसे-जैसे सख्ती बढ़ती गई अपराधियों ने भी नए-नए पैतरे आजमाने शुरू कर दिए। लेकिन इस दिशा में पुलिस अभी तक पूरी तरह से सजग नहीं हो पाई है। साइबर सेल का अलग विभाग बना देने के बाद भी वहाँ अपने मोबाइल के खेजे जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहीं बार चक्कर लगवाया जाता है। कुल मिलाकर पुलिस इस दिशा में अभी तक सचेत नहीं हुई है। इसलिए साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद भी पुलिस अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। इस अपराध में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आधिनिक तकनीकी की पूरी जानकारी नहीं रखते। थाई-सी ही जानकारी के आधार पर लोग अपने डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग असावधानीकृत करते रहते हैं। इस अपराध में अपराधी सामने

जनता यह नहीं सोचती कि आजकल कोई आपको मुफ्त में एक कप चाय नहीं पिलाता, तो फिर वह क्यों केवल आपको लाखों रुपये यूं ही दे देगा। ये अपराधी मानव के भीतर की लालसा को जगाकर उनसे ठंगी कर लेते हैं। बैंक द्वारा बार-बार यह आग्रह किया जाता है कि किसी अनजान को कभी अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या ओटीपी न दें। बैंक कभी किसी से फोन पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मांगती। फिर भी लोग लालच में आकर ठंगी का शिकार हो जाते हैं। व्यापार में पूँजी निर्माण के लिए और अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। वैश्विक स्तर पर कारपोरेट बिजेनेस में साइबर ठंगी की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक अनुपान के अनुसार देश में सालाना लगभग 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान साइबर ठंगी के कारण हो रहा है। इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ऊपर हैं।



आदर और गहरी दोस्ती है। 29 जनवरी, 1992 को औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से इजारायल और भारत ने मिलकर जो हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। हमारी दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। भारत का यहूदी समुदाय इन संबंधों की आधारशिलाओं में से एक है। यहूदी पीढ़ियों से भारत में शांति के साथ रह रहे हैं। उन्हें कभी ऐं अंतरिक्ष इनमें प्रमुख है। भारत हमारा अब केवल धनिष्ठ मित्र ही नहीं है, बल्कि एक सामरिक साझेदार भी है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों औं प्रधानमंत्रियों के साथ अनेक उच्च स्तरीय दौरों से यह स्पष्ट भी हो जाता है। आने वाले वर्षी में और अधिक उच्च स्तरीय दौरों की योजना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत हमारे प्रमुख साझेदारों में से एक है। आज हमारे द्विपक्षीय संबंध जिन क्षेत्रों में केंद्रित

A person wearing a mask and hood, sitting at a desk and working on a computer. The scene is dimly lit with blue light, suggesting a dark or nighttime environment.

का रवैया ढिला-ढाला ही रहा है। लिहाजा साइबर ठंगी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। व्यापार-उद्योग तथा दैनंदिन जीवन में डिजिटल ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उस तेजी से साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का उपयोग नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम या आनलाइन ठंगी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे साइबर क्राइम के कारण साइबर सिक्योरिटी एक नई इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। अब देश भर में साइबर सिक्योरिटी का बाजार ढेंडलाख करोड़ रुपये वार्षिक पार कर विदेश में बैठकर भी यह अपराध कर लेता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन साइबर अपराधियों को मौका मिल जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में लालच का भाव भरा हुआ है। मुफ्त में मिलने वाली किसी भी चीज के लिए वे इन्कार नहीं करते। इसलिए वे प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं अपराधी उनकी इसी कमज़ोरी का पूरा फायदा उठाते हुए उन्हें ठग लेते हैं सामान्य जनता आधुनिक समाजधनों का खूब इस्तेमाल करती है, पर सजगता नहीं होने के कारण वह अक्सर ठंगी का शिकार हो जाती है।

